लेने के पश्चात कई बार हम लोगों को मौका भी मिला है, समितियों के माध्यम से जब जानकारी करने की कोशिश की गयी तो बैंकों की ओर से, जिस ढंग से कर्जे देने की बात आनी चाहिए, उसमें बड़ी उदासीनता दिखायी पड़ी है। महोदय, कृषि ऋण का इन्होंने 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपया बढ़ाने का प्रस्ताव जरूर किया है लेकिन पिछली बार जो 1 लाख 41 हजार 500 करोड़ का लक्ष्य था, वह लक्ष्य भी पूरा हुआ या नहीं हुआ, सुनिश्चित रूप से यह जानकारी भी आवश्यक है। दो फीसदी कृषि वृद्धि, फसल उत्पादन में आया ठहराव मानसून पर निर्भर जरूर करता होगा लेकिन किसानों की व्यवस्था की दृष्टि से जो और सुविधाएं उनको प्रदान करनी चाहिए - एनडीए सरकार के दौरान हमने कई सुविधाएं किसानों को दी थीं, फसल आय बीमा योजना, यह सब हमने सुनिश्चित किया था - उसको प्रभावी तौर पर लागू करने की बात होनी चाहिए। किसानों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके लिए जो कर्जे लेते हैं, उसकी ब्याज दर 9 फीसदी है। महोदय, इसको भी घटाकर कम करना चाहिए, उसी के अनुरूप करना चाहिए ताकि किसान अनुभव कर सकें कि हमें हर तरीके से सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ किसी भी प्रकार की विभेदकारी स्थिति निर्मित होना उचित नहीं होगी। अभी अल्पसंख्यकों के लिए, उनके शिक्षण संस्थानों के लिए बजट की व्यवस्था की गयी है, उर्दू भाषा के लिए दस करोड़ से बढ़ाकर 13 करोड़ किया गया है। लेकिन संस्कृत भाषा के लिए कहीं उल्लेख भी नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि संस्कृत के विकास के लिए भी बजट का समुचित तौर पर आवंटन आवश्यक है।

मान्यवर, यह सब देखने के पश्चात मैं कह सकता हूं कि जिस ढंग से बजट का आवंटन किया गया है, हर दृष्टि से जो बात की गई है, सेवा-कर में जो बढ़ोत्तरी की गई है, उसके कारण महंगाई आसमान छूने लगी है। आम आदमी को इसने प्रभावित किया है और इस सेवा-कर में दस फीसदी से बारह फीसदी की बढ़ोत्तरी होने पर, एक-एक व्यक्ति पर तीन सौ रुपए तक का बोझ पड़ सकता है, वह प्रभावित हो सकता है। इसलिए जहां छूट देने की बात की गई है, एक्साइज़ ड्यूटी में भले ही कुछ छूट दी गई होगी, उससे कोई बहुत अधिक लाभ आम आदमी को होगा, यह तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके कारण आम आदमी तबाह ज़रूर हो रहा है और आम आदमी को तबाही देने वाला इस बजट का स्वरूप बन गया है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री इस पर विचार करते हुए, निश्चित रूप से जो आम आदमी को सेवा-कर इस ढंग से प्रभावित कर रहा है, उससे मुक्ति दिलाएं। यह सब देखने के पश्चात मैं कह सकता हूं कि बजट, जो आम आदमी के लिए उपयोगी होना चाहिए, जिसमें गरीब आदमी को केंद्र में रखकर उसकी समुचित व्यवस्था करने की बात होनी चाहिए, उस दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं है। यह कहते हुए, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

STATEMENT BY MINISTERS - *Contd.*

Status of implementation of recommendations contained in Third, Seventh and Ninth Reports of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Energy

THE MINISTER OF POWER (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Sir, I lay on the Table a statement regarding the Status of implementation of

recommendations contained in the Third, Seventh and Ninth Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Energy.

Status of implementation of recommendations contained in one hundred and sixty-third report of Department-Related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): Sir, I lay on the Table a statement regarding the Status of implementation of recommendations contained in the One Hundred and Sixty-third Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development.

Status of implementation of recommendations contained in eighth report of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Coal and Steel

कोयला मंत्री (श्री शिबू सोरेन) : महोदय, मैं विभाग-संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

THE BUDGET (GENERAL), 2006-2007 - *Contd.*

श्री उपसभापति : श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, आपके सिर्फ दस मिनट हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (हरियाणा) : सर, हम तो others में आते हैं, अगर आप हमें दो मिनट भी दे दें, तो हम उसके लिए भी शुक्रगुज़ार हैं।

उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। अगर रेलवे विभाग का अलग बजट हो सकता है, तो मेरा पहला अनुरोध तो यह है कि कृषि पर अलग बजट होना चाहिए, यह परंपरा यहां डालनी होगी, ताकि किसानों की उन्नति हो सके, किसानों की तरक्की हो सके, इसलिए कृषि के लिए अलग बजट बनाने का काम करें, ऐसा मेरा अनुरोध है।

मान्यवर, मैंने बजट को ध्यानपूर्वक देखा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरा ज्ञानवर्द्धन होगा - छोटी कार पर आपने एक्साइज़ घटाई, उससे राष्ट्र की क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यह वे अपने उत्तर में यह बता दें, तुलनात्मक बता दें। यदि इसके स्थान पर वे ट्रैक्टर को एक्साइज़ मुक्त कर देते तो क्या कृषि की उत्पादकता बढ़ती या नहीं बढ़ती? देश की तरक्की का रास्ता प्रशस्त होता या नहीं होता? मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि छोटी कार पर जो उन्होंने एक्साइज़ घटाया है, वह तो उनका फैसला है, लेकिन लोग तो कृषि से ज्यादा जुड़े हैं। उद्योगपति ज़रूर कार से जुड़ा है। जो कार बनाता है, उसकी कार सस्ती